भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4843
1 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात आयात की गुणवत्ता

4843. श्री अरुण भारती:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की अपवंचना करने वाले इस्पात के आयात की मात्रा और गुणवत्ता से संबंधित ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता प्राप्त कर लेने के आर्थिक लाभों का, विशेषकर से छोटे और मध्यम इस्पात उत्पादकों के लिए, आकलन किया है और यदि हां, तो इसके अपेक्षित परिणाम और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीआईएस मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के प्रवर्तन से घटिया इस्पात के आयात में प्रभावी रूप से कमी आई है और यदि हां, तो घरेलू इस्पात की कीमतों और उसके उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) एनओसी आवेदनों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के लिए मौजूदा ऑनलाइन पोर्टल का विस्तार या उन्नयन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात के उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट प्रोत्साहन या नीतियां राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुरूप हैं और यदि हां, तो इसके लिए क्या पहल की गई है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क), (ग) और (घ): इस्पात उत्पाद के लिए जब भी बीआईएस मानक तैयार किया जाता है और उसे इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीओ) आदेश में शामिल किया जाता है, तो घरेलू उत्पादकों अथवा भारत को निर्यात करने के इच्छुक विदेशी उत्पादकों द्वारा ऐसे इस्पात उत्पाद का विनिर्माण बीआईएस अनुज्ञप्ति के साथ किया जाना अनिवार्य है। अब तक कार्बन इस्पात, मिश्रधातु इस्पात और स्टेनलेस स्टील को शामिल करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत 151 भारतीय मानक अधिसूचित किए गए हैं।

एनओसी आवेदनों के लिए मौजूदा ऑनलाइन पोर्टल को अपग्रेड करने हेतु किए गए उपायों के संबंध में, ऐसे उत्पाद जो क्यूसीओ के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, के लिए एनओसी चाहने वाले आवेदकों हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) पोर्टल के साथ कार्यपद्धति को एकीकृत किया गया था। इस पहल ने व्यापार में सरलता को बढ़ावा दिया, क्योंकि आयातकों को केवल एक ही पोर्टल पर पंजीकरण करना और वांछित इनपुट प्रदान करना होता है।

जारी...2/-

इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और घरेलू इस्पात की कीमतें और इस्पात उत्पादन, इस्पात निर्माण की क्षमता, बाजार की शक्तियों की मांग और आपूर्ति संबंधी गतिशीलता, खपत आदि जैसे कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं।

(ख): राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 में लघु एवं मध्यम इस्पात उत्पादकों सहित प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।

(ङ) राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुरूप टिकाऊ एवं उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इस्पात मंत्रालय की निम्नलिखित पहलें हैं:-

- सरकार ने पूंजी निवेश को आकर्षित करके और इस्पात क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देकर देश के भीतर कुछ उच्च ग्रेड किस्मों के इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु 'विशेष इस्पात' के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत, इस्पात मंत्रालय ने इस मिशन के तहत कोयले/कोक की खपत को कम करने के लिए वर्टिकल शाफ्ट में 100% हाइड्रोजन का उपयोग करके डीआरआई का उत्पादन करने के लिए दो पायलट परियोजनाएं और मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन का उपयोग करने हेतु एक परियोजना प्रदान की है।

*****